अनुमान से 10% कम रह सकता है शुगर प्रॉडक्शन

[ईटी ब्यूरो | पुणे & नई दिल्ली]

महाराष्ट्र में जहां पेराई सीजन खत्म होने को है, वहीं इंडस्ट्री के दिग्गजों को लग रहा है कि देश में शुगर प्रॉडक्शन सरकार के अनुमान से 10 फीसदी कम रह सकता है। केंद्र सरकार ने जहां 2016-17 के लिए 2.25 करोड़ टन शुगर प्रॉडक्शन का अनुमान जताया है, वहीं इंडस्ट्री को अब लगता है कि वास्तविक प्रॉडक्शन करीब 2 करोड़ टन रह सकता है।

राज्य सरकार के हालिया आंकड़ों के मुताबिक, 20 फरवरी तक महाराष्ट्र की शुगर मिलों ने 40.56 लाख टन शुगर का उत्पादन किया, जबकि पिछले साल के इसी पीरियड में उत्पादन 65.62 लाख टन था।

जिन 150 शुगर मिलों ने इस साल गन्ने की पेराई का काम शुरू किया, उनमें से 124 मिलें गन्ना उपलब्ध नहीं होने के कारण पहले ही बंद हो चुकी हैं। सिर्फ 26 मिलें अब शुगर का प्रॉडक्शन कर रही हैं, जबकि पिछले साल के इसी पीरियड में 121 मिलें चल रही थीं।

इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक, 15 फरवरी को देश का शुगर डेफिसिट बढ़कर 15 फीसदी तक पहुंच चुका था, जबकि 31 जनवरी को यह आंकड़ा 10 फीसदी था। इस संस्था ने 2016-17 में शुगर की खपत 2.40-2.43 करोड़ टन के दायरे में रहने का अनुमान जताया है। केंद्र सरकार का अनुमान है कि भारत का शुगर प्रॉडक्शन 2.25 करोड़ टन रहेगा और वह महाराष्ट्र के प्रॉडक्शन और सेल्स आंकड़ों पर करीबी नजर बनाए हुए है। 2017 में शुगर की घरेलू कीमत तय करने में यह मामला काफी अहम होगा।

इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ओ पी धानुका ने बताया, 'अब ऐसा लगता है कि देश का शुगर प्रॉडक्शन 2.03 करोड़ टन रह सकता है। इसके बावजूद हमारे पास घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त शुगर होगा और हमें इसके इंपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।'

गन्ने की बकाया रकम चुकाएं चीनी मिलें: सरकार

फूड मिनिस्ट्री ने चीनी मिलों से शुगर ईयर 2015-16 के लिए गन्ने की बकाया रकम को क्लीयर करने के साथ 2016-17 की बकाया रकम का भी जल्द भुगतान करने को कहा है। मिनिस्ट्री के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उन्होंने मिलों से चीनी का स्टॉक जारी करते रहने और उसकी होर्डिंग न करने को कहा है। इसके अलावा उनसे कंज्यूमर्स के लिए प्राइस में वृद्धि नहीं करने के लिए भी कहा गया है।

अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से तय फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस (FRP) के लिहाज से सितंबर 2016 में समाप्त हुए 2015-16 के सीजन के लिए मिलों पर किसानों की 334 करोड़ रुपये की रकम बकाया है, जबकि राज्य सरकारों के स्टेट एडवाइज्ड प्राइस (SAP) के तहत यह रकम करीब 1,206 करोड़ रुपये की है। इसमें से अधिकतर बकाया रकम तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों की है। इस बारे में डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की सेक्रेटरी प्रीति सूदन ने मंगलवार को शुगर इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों और इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (ISMA) के पदाधिकारियों के साथ मंगलवार को मीटिंग की।

Economic Times.
22-2-17